

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3234

बुधवार, 9 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूकंप के संबंध में जागरूकता

†3234. श्री संजय काका पाटील:  
श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:  
श्री मारगनी भरत:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश की 59 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र के मध्यम तीव्रता वाले अथवा तीव्रता वाले भूकंपों की चपेट में आने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो भूकंप के दौरान अनुक्रिया करने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन प्रयासों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;
- (ग) क्या भारत में सर्वाधिक भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों का निर्धारण करने और उनके सुरक्षोपाय हेतु कोई अध्ययन या जांच की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से तैयारी में सुधार लाने, जैसे प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी ज्ञान का प्रसार करने हेतु कोई अतिरिक्त कदम उठाए हैं; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

पृथ्वी विज्ञान मंत्री  
(श्री किरेन रिजिजू)

- (क) जी हाँ। पूरे देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात जोन V (उच्चतम भूकंपीय सक्रिय), IV, III और II (सबसे कम भूकंपीय सक्रिय)में विभाजित किया गया है। भारत का कुल ~59% भूभाग (भारत के सभी राज्यों को कवर करते हुए) अलग-अलग झटकों की तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। देश के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, देश का ~11% क्षेत्र जोन V में, ~17% जोन IV में, ~31% जोन III में और शेष भाग जोन II में आता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र अनुलग्नक-I में संलग्न है।
- (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) नियमित रूप से भूकंप जागरूकता अभियान चलाते हैं और पूरे देश में राहत और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के सहयोग से माॅक ड्रिल आयोजित करते हैं। ये अभियान, जनता को भूकंप की रोकथाम और तैयारी के उपायों के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं।

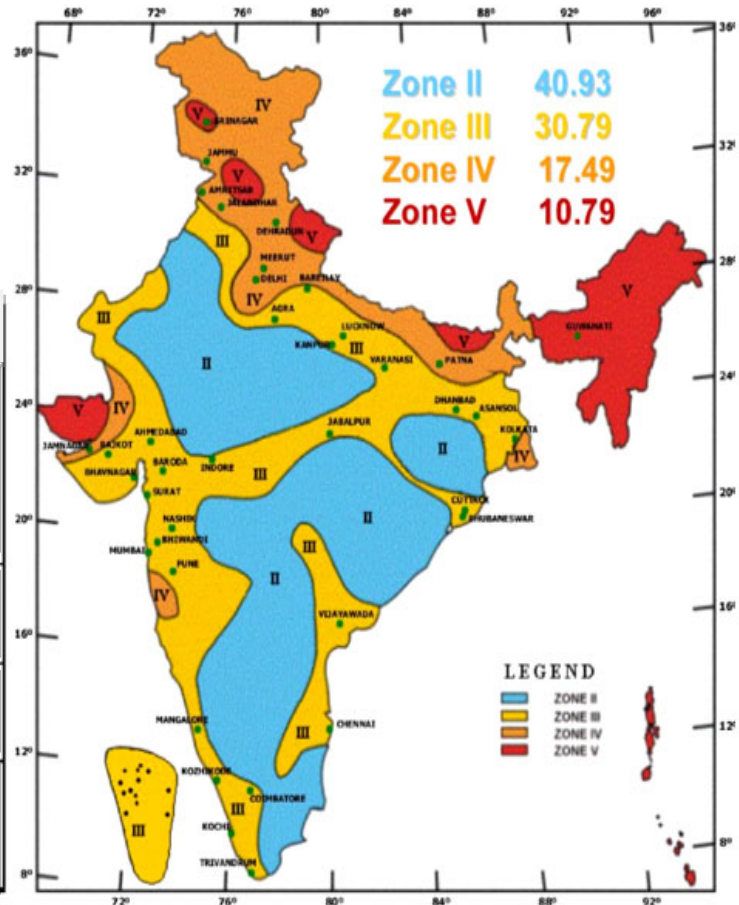
(ग) और (घ) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है जिसे भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के रूप में जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से पूरे भारत में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भूकंपीय जोखिमों का आकलन करना है। भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूकंप के झटकों के प्रभावों को कम करने और सुरक्षित शहरी नियोजन के लिए संरचनाओं को होने वाले नुकसान और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए भूकंप जोखिम प्रतिरोधी इमारतों/बुनियादी ढांचे/आवासों के निर्माण के लिए इनपुट सृजन करने में मदद करता है। इस संबंध में दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और गंगटोक जैसे प्रमुख शहरों के लिए व्यापक अध्ययन किए गए हैं। इन आकलनों के निष्कर्षों को रेखांकित करने वाली विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इन भूकंपीय क्षेत्रों के आधार पर संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। NDMA, NIDM और अन्य संबंधित अधिकारी लोगों को भूकंप की तैयारी, प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। इन अभियानों में आपातकालीन किट बनाने, निकासी अभ्यास आयोजित करने और घरों के भीतर फर्नीचर और भारी वस्तुओं को सुरक्षित करने की जानकारी शामिल है।

(ङ) और (च) सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए समग्र, एकीकृत और प्रभावी दृष्टिकोण के लिए आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 लागू किया। DM अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया करने के लिए अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), आपदा मित्र और अन्य प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता जैसे संगठन किसी भी आपदा के दौरान तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू करते हैं।

**भूकंपीय जोन**  
भारत का मानचित्र - 2002

भारत का लगभग **59 %**  
भूभाग भूकंपीय जोखिम हानि  
के लिए जिम्मेदार है।

जोन	तीव्रता
जोन V	बहुत उच्च जोखिम जोन क्षेत्र तीव्रता IX (और ऊपर) के लिए जिम्मेदार
जोन IV	उच्च जोखिम जोन तीव्रता VIII
जोन III	मध्यम जोखिम जोन तीव्रता VII
जोन II	निम्न जोखिम जोन तीव्रता VI (और कम)



चित्र 1 भारत का भूकंपीय जोन क्षेत्र और भूकंप तीव्रता मानचित्र

\*\*\*\*\*